प्रस्ताव
39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश — अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण। पहल अधिनियम।

- बहुराज्य व्यवसायों को कैलिफोर्निया में उनकी बिक्री के प्रतिशत के आधार पर उनकी कैलिफोर्निया आयकर देयता की गणना करने की मांग करता है।
- बहुराज्य व्यवसायों को कर देयता फार्मूला चुनने का विकल्प देने वाले मौजूदा कानून को भंग करता है जो कि कैलिफोर्निया के बाहर संपत्ति और पेरोल वाले व्यवसायों को अनुकूल कर उपचार प्रदान करता है।
- राजस्व में प्रत्याशित वृद्धि से पाँच वर्ष के लिए सालाना $550 मिलियन को ऐसी परियोजनाओं में धन लगाने के लिए समर्पित करता है जो कैलिफोर्निया में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा नौकरियां तैयार करती हैं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव का वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सार:

- बहुराज्य व्यवसायों की इस बारे में चुनाव करने की क्षमता को खत्म करके कि उनकी कैलिफोर्निया कर योग्य आय को कैसे निर्धारित किया जाता है, अतिरिक्त वार्षिक राज्य राजस्व में लगभग $1 बिलियन—जो समय के साथ बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ बहुराज्य व्यवसाय अधिक राज्य करों का भुगतान करेंगे।
- अगले पांच वर्षों में इस उपाय द्वारा इक्ट्ठे किए गए राजस्व में से, लगभग आधे को ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित किया जाएगा।
- शेष राजस्व में से, एक बड़े भाग की पब्लिक स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों पर खर्च किए जाने की संभावना है।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

स्टेट कार्पोरेट आयकर। वह धनराशि जो एक व्यवसाय प्रतिवर्ष कार्पोरेट आयकरों में राज्य को देता है व्यवसाय के करयोग्य आय पर आधारित होती है। ऐसे व्यवसाय के लिए जिनका संचालन कैलीफोर्निया और दूसरे राज्यों या देशों दोनों में होता है (बहुराज्य व्यवसाय), राज्य कर उसके केवल उन आयों का हिस्सा है जो कैलीफोर्निया से जुड़े हैं। जबकि निगमों का केवल एक छोटा हिस्सा प्रकृति में बहुराज्य है, बहुराज्य निगम राज्य के कारपोरेट आयकरों के बड़े हिस्से का भुगतान करते हैं। यह कर राज्य का तीसरा सबसे बड़ा सामान्य कोष राजस्व स्रोत है, जो 2010–11 में बढ़कर $ 9.6 बिलियन हो गया।

बहुराज्य व्यवसाय यह चुनते हैं कि उनके करयोग्य आय का निर्धारण कैसे हो। इस समय, राज्य कानून ज्यादातर बहुराज्य व्यवसायों को कैलीफोर्निया से जुड़े उनके आय और राज्य द्वारा करयोग्य राशि के निर्धारण के लिए दो में से एक तरीका अपनाने की अनुमति देता है:

- ***कर योग्य आय के निर्धारण के "तीन- कारक तरीके"।*** एक तरीका कंपनी की बिक्री का स्थान, उसकी संपत्ति और कर्मचारियों का उपयोग करता है। इस तरीके का इस्तेमाल करते समय, ज्यादा बिक्री, संपत्ति,या कर्मचारी जो बहुराज्य व्यवसाय के पास कैलीफोर्निया में हैं, व्यवसाय की आय का ज्यादा हिस्सा राज्य कर का मामला होता है।

- ***कर योग्य आय के निर्धारण का "एकल बिक्री कारक तरीका"।*** दूसरा तरीका केवल कंपनी की बिक्री के स्थान का उपयोग करता है। इस तरीके का उपयोग करते हुए, बहुराज्य व्यवसाय कैलीफोर्निया में जितना अधिक बिक्री करता है, व्यवसाय के अपेक्षया अधिक आय पर कर लगता है। (उदाहरण के लिए, यदि कंपनी के उत्पाद का एक-चौथाई हिस्सा कैलीफोर्निया में बेचा जाता है और बाकी दूसरे राज्यों में, कंपनी के कुल लाभ का एक-चौथाई कैलीफोर्निया कर निर्धारण का मामला होगा।)

बहुराज्य व्यवसायों को आम तौर पर उस तरीके को चुनने की अनुमति दी जाती है जो कर उद्देश्यों से उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हो।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। ऊर्जा खपत कम करने के लिए इस समय कई कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं। इन प्रयासों का इरादा ऊर्जा के नए बुनियादी ढांचे (जैसे कि बिजली संयत्र और पारेषण लाइन) के निर्माण की आवश्यकता कम करने और पर्यावरण की गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने में मदद करने का है। उदाहरण के लिए, कैलीफोर्निया पब्लिक युटिलिटी कमिशन (CPUC) विभिन्न प्रकार के ऊर्जा दक्षता उन्नयन और उपकरण छूट कार्यक्रमों की देखरेख करता है जिनका वित्त पोषण उपयोगिता करदाताओं से एकत्र धन द्वारा होता है। इसके अलावा, कैलीफोर्निया एनर्जी कमिशन (CEC) भवन एवं उपकरण मानक विकसित करता है जिसका मकसद राज्य में ऊर्जा खपत कम करना होता है।

स्कूल अनुदान फार्मूला। प्रस्ताव 98, मतदाताओं द्वारा 1988 में पारित और 1990 में संशोधित, पब्लिक स्कूलों और कम्यूनिटी कॉलेजों (यहां बाद में जिन्हें स्कूल कहा गया है) के लिए हर साल राज्य और स्थानीय अनुदान एक न्यूनतम स्तर चाहता है। यह अनुदान स्तर प्रस्ताव 98 की न्यूनतम गारंटी के तौर पर जाना जाता है। यद्यपि विधानमंडल गारंटी और निधि को एक निचले स्तर पर स्थगित कर सकता है, यह खास तौर पर गारंटी के बराबर अथवा उससे ज्यादा वित्त पोषण उपलब्ध कराने का फैसला करता है। प्रस्ताव 98 की गारंटी राज्य के सामान्य कोष राजस्वों (इसमें वह राशि भी शामिल है जो राज्य कार्पोरेट आयकर से एकत्र की गई है) में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। इसी प्रकार, एक उपाय—जैसे कि यह—जिससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, के परिणामस्वरूप स्कूल वित्त पोषण गारंटी भी ज्यादा हो सकती है। प्रस्ताव 98 के व्यय राज्य बजट के सबसे ज्यादा खर्चे वाली श्रेणी में आते हैं—कुल राज्य के सामान्य कोष व्यय का लगभग 40 प्रतिशत।

प्रस्ताव

बहुराज्य व्यवसायों की यह चुनने की क्षमता खत्म करता है कि कर योग्य आय का निर्धारण कैसे हो। सन 2013 में शुरू हो रहे इस उपाय के तहत, बहुराज्य व्यवसायों को ज्यादा समय तक यह अनुमति नहीं होगी कि वे अपने राज्य कर योग्य आय के निर्धारण का चुनाव करें जो कि उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। इसके बजाय, ज्यादातर बहुराज्य व्यवसायों को एकल बिक्री कारक तरीका अपनाते हुए अपने कैलीफोर्निया कर योग्य आय का निर्धारण करना होगा। कैवल कैलीफोर्निया में संचालित होने वाले व्यवसाय इस उपाय से प्रभावित नहीं होंगे।

इस उपाय में इस संबंध में नियम भी शामिल हैं कि सभी बहुराज्य व्यवसाय कुछ बिक्री के हिस्से की गणना कैसे करते हैं जो राज्य कर उद्देश्यों के लिए कैलीफोर्निया को आवंटित किए गए हैं। इनमे कुछ निश्चित बड़ी केबल कंपनियों के लिए विशिष्ट नियम शामिल हैं।

ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है। यह उपाय ऊर्जा दक्षता में सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग में विस्तार के इरादे वाली परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक नया राज्य कोष, स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष, स्थापित करता है। उपाय यह कहता

प्रस्ताव 39 के पाठ के लिए, पृष्ठ 125 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

है कि कोष का उपयोग निम्न के समर्थन में किया जा सकता है: (1)पब्लिक स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता "रेट्रोफिट्स" और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं; (2) ऊर्जा "रेट्रोफिट्स" के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग; और (3) ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी रोजगार प्रशिक्षण व कार्यबल विकास कार्यक्रम। विधानमंडल कोष से खर्च का निर्धारण करेगा और ऊर्जा परियोजनाओं के प्रबंधन में माहिर एजेंसियों द्वारा संचालित किफायती परिजनाओं के लिए धन के उपयोग में उसकी जरूरत रहेगी। यह उपाय (1) स्पष्ट तौर पर बताता भी है कि सभी वित्त पोषित परियोजनाओं को CEC और CPUC से समन्वय करना होगा और (2) कोष से खर्चे की सालाना समीक्षा और मूल्यांकन के लिए नये नौ-सदस्यीय निगरानी बोर्ड का गठन भी करता है।

स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को अनिवार्य एकल बिक्री कारक के संचालन द्वारा एकत्र कुछ नये राजस्व से सहायता मिलेगी। खास तौर पर, इस तरह एकत्रित राजस्वों का आधा हिस्सा—अधिकतम $550 मिलियन तक—सालाना स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये स्थानांतरण केवल पांच वित्तीय वर्षों—2013–14 से 2017–18 तक के लिए होंगे।

वित्तीय प्रभाव

राज्य राजस्व में वृद्धि। जैसा कि चित्र 1 के शीर्ष लाइन में दिखाया गया है, यह उपाय राज्य राजस्व में $1 बिलियन सालाना वृद्धि करेगा जो 2013–14 में शुरू हो रहा है। (2012-13 में लगभग आधे साल का प्रभाव रहेगा।) बढ़े राजस्व ज्यादा कर दे रहे कुछ बहुराज्य व्यवसाय से आएंगे। इस उपाय से एकत्रित राशि समय के साथ बढ़ेगी।

ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयोग होने वाले कुछ राजस्व। पांच साल की अवधि (2013–14 से 2017–18 तक) के लिए, अतिरिक्त राजस्व का लगभग आधा —$500 मिलियन से $550 मिलियन सालाना—ऊर्जा दक्षता और

चित्र 1
राज्य राजस्वों और खर्च पर प्रस्ताव 39 के प्रभाव का अनुमान

	2012–13	2013–14 से 2017–18 तक	2018–19 और उसके बाद
सालाना राजस्व	$500 मिलियन	$1 बिलियन, समय के साथ वृद्धि	$1 बिलियन से ज़्यादा
सालाना खर्च			
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित राशि	कुछ नहीं	$500 मिलियन से $550 मिलियन	कुछ नहीं
स्कूल वित्त पोषण गारंटी में वृद्धि	$200 मिलियन से $500 मिलियन तक	$200 मिलियन से $500 मिलियन, समय के साथ वृद्धि	$500 मिलियन से $1 बिलियन से ऊपर

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन के लिए स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त राजस्व के कारण स्कूल वित्त पोषण बढ़ने की संभावना। सामनयतः, उपाय से एकत्रित राजस्व को राज्य के सालाना प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी की गणना में माना जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को स्थानांतरित कोष, हालांकि, का उपोयोग इस गणना में नहीं किया जाएगा। जैसाकि चित्र 1 के निचले हिस्से में दिखाया गया है, ज्यादा राजस्व 2012–13 से 2017–18 तक की अवधि के लिए कम से कम $200 मिलियन तक न्यूनतम गारंटी संभवतः बढ़ाएगा। इस अवधि के कुछ वर्षों में, हालांकि न्यूनतम गारंटी उल्लेखनीय रूप से ज्यादा हो सकती है। 2018–19 और उसके बाद के लिए, गारंटी के कम से कम $500 मिलियन ज्यादा होने की संभावना है। शुरुआती अवधि की तरह, गारंटी कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से ज्यादा हो सकती है। किसी खास वर्ष स्कूलों को जाने वाला एकत्रित राजस्व का सही-सही हिस्सा विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें राज्य राजस्व में संपूर्ण वृद्धि और उल्लेखनीय रूप से स्कूल वित्त पोषण दायित्वों का आकार शामिल है।

प्रस्ताव 39 के पाठ के लिए, पृष्ठ 125 देखें।